

8- f' k{kk

सैक्टर एक दृष्टि में

वार्षिक योजना वर्ष 2014–2015 में योजना हेतु प्रस्तावित राशि

● आयोजना बजट सीलिंग राशि	23152.96 लाख
● राज्य आयोजना मद	19474.13 लाख
● केन्द्रीय योजना मद	3678.83 लाख

लक्ष्य एवं उद्देश्य

- औपचारिक विद्यालयों/वैकल्पिक विद्यालयों एवं राजीव गांधी पाठशालाओं का सुदृढीकरण।
- सन् 2003 तक 6–14 आयुवर्ग के सभी शिक्षा से वंचित बालक बालिकाओं का नामांकन एवं जुड़ाव सुनिश्चित करना।
- न्यूनतम अधिगम स्तर की प्राप्ति तथा सबको समान एवं निशुल्क प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति सुनिश्चित करना।
- जीवनोपयोगी तथा प्रासंगिक पाठ्यक्रम के निर्माण एवं आनन्ददायी वातावरण में शिक्षा देने पर विशेष बल।
- विद्यालयों में ठहराव दर 100 प्रतिशत करना।
- सकल नामांकन दर को 100 प्रतिशत करना।
- शालाओं की मरम्मत एवं जरूरतमंद स्कूलों में शौचालय एवं शुद्ध पेयजल तथा चार दीवारी की सुविधाएं उपलब्ध कराना।
- जन सहभागिता द्वारा भौतिक एवं अकादमिक गतिविधियों को सुदृढ किया जाना।
- अनौपचारिक शिक्षा की मुख्य धारा से किन्हीं कारणों से वंचित बच्चों की शिक्षा हेतु विशेष व्यवस्था करना तथा इन्हें गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करना।
- शाला से वंचित एवं बीच में ही शाला छोड़ देने वाली बालिकाओं को उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराना।
- खेल एवं क्रिया आधारित शिक्षण तथा जीवनोपयोगी शिक्षा एवं स्थानीय आवश्यकताओं हेतु संसाधन उपलब्ध कराना।
- बालकों को दरी पट्टी तथा विद्यालयों को फर्नीचर एवं अन्य शैक्षिक उपकरण उपलब्ध कराना।
- शिक्षा की उपयोगिता तथा गुणवत्ता में वृद्धि करने हेतु शिक्षकों को बौद्धिक तथा मानसिक सम्बलन प्रदान करने एवं व्यावसायिक दक्षता के उन्नयन हेतु प्रभावी एवं दक्ष प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण एवं अभिप्रेरण की व्यवस्था करना।
- बालकों के न्यूनतम अधिगम स्तर में वृद्धि करने हेतु पाठ्यक्रम तैयार करना तथा उसके अनुरूप शिक्षण हेतु शिक्षकों को प्रेरित करना।
- विद्यालयों के प्रबंधन में जन सहभागिता सुनिश्चित करना।

शिक्षा विभाग का दृष्टि पत्र

8.1 वर्तमान स्थिति

	नागौर	राजस्थान
■ साक्षरता दर	57.3	60.4
■ नामांकन दर	58.7	67.6
■ प्राथमिक विद्यालय प्रति एक हजार व्यक्ति	1.09	
■ उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रति एक हजार व्यक्ति	0.30	
■ माध्यमिक विद्यालय प्रति दस हजार व्यक्ति	0.81	
■ उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रति दस हजार व्यक्ति	0.28	
■ शिक्षक छात्र अनुपात	1.33	
■ जिले में 6-14 आयुवर्ग के बालको की जनसंख्या	342313	
■ जिले में 6-14 आयुवर्ग के बालिकाओं की जनसंख्या	284616	
■ जिले में 6-14 आयुवर्ग के बालको का नामांकन 06-07	341345	
■ जिले में 6-14 आयुवर्ग के बालिकाओं का नामांकन 06-07	281215	
■ जिले में संचालित विद्यालयों का पंचायत समिति/नगरीय क्षेत्रवार विवरण		

8.1.1 शिक्षण संस्थाओं की संख्या

ब्लॉक वार

क्र. सं.	प.सं./नगर	उ.मा.वि.	मा.वि.	उ.प्रा.वि.	प्रा.वि.	व्या. एवं विशेष शिक्षा हेतु स्कूल	अन्य	योग
1	नागौर	7	22	84	156	0	100	369
2	जायल	9	24	69	101	0	86	289
3	मूण्डवा	6	21	62	105	0	142	336
4	लाड़नूँ	6	22	51	85	0	22	186
5	डीडवाना	15	36	95	171	0	158	475
6	कुचामन	11	25	82	168	0	86	372
7	परबतसर	6	20	69	104	0	78	277
8	मकराना	7	26	68	119	0	108	328
9	डेगाना	8	19	66	119	0	95	307
10	रियॉबड़ी	6	17	62	91	0	95	271
11	मेड़तासिटी	5	23	50	104	0	31	213
योग		86	255	758	1323	0	1001	3423

नगरीय क्षेत्रवार

1	नागौर	10	18	3	17	0	13	61
2	लाड़नूँ	6	5	4	5	0	0	20
3	डीडवाना	4	9	6	10	0	2	31
4	कुचामन	8	9	10	17	0	2	46
5	नॉवा	2	1			0		3
6	परबतसर	3	1	2	8	0	4	18
7	मकराना	6	9	3	12	0	0	30
8	मेड़तासिटी	3	6	2	4	0	8	23

9	मूण्डवा	3	0	3	6	0	6	18
10	कुचेरा	1	4			0		5
योग		46	62	33	79	0	35	255
महायोग		132	317	791	1402	0	1036	3678

8.1.2 प्रारम्भिक शिक्षा/सर्व शिक्षा अभियान

- **विद्यालय** – वर्तमान में जिले में प्रारम्भिक स्तर की 2629 राजकीय विद्यालय एवं 210 निजी विद्यालय संचालित है। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के 1236 राजकीय एवं 879 गैर राजकीय विद्यालय संचालित है।
- **पूर्णता दर एवं संक्रमण दर** – वर्तमान में जिले की पूर्णता दर 85.79 प्रतिशत है, इसी प्रकार प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर में संक्रमण दर 95.26 प्रतिशत है।
- **जीईआर एवं एनईआर** – वर्तमान में 6-11 आयुवर्ग के बालक/बालिकाओं की जीईआर दर 102.68 व एनईआर दर 98.37 है। इसी प्रकार 11-14 आयुवर्ग के बालक/ बालिकाओं की जीईआर दर एवं एनईआर दर 98.6 प्रतिशत है।
- **अध्यापक एवं पीटीआर** – वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में 5277 अध्यापक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 5310 शिक्षक कार्यरत है। नामांकन के हिसाब से पीटीआर प्राथमिक स्तर पर 37.30 है, जबकि उच्च प्राथमिक स्तर पर 36.12 है।
- **विद्यालय सुविधा** – वर्तमान में प्रारम्भिक स्तर के संचालित 2527 राजकीय विद्यालयों में से 47 विद्यालय भवन रहित है, साथ ही इन विद्यालयों में 5000 कक्षा कक्ष है।

8.1.3 नागौर जिले में वर्तमान विद्यालयों की स्थिति :-

क्र.सं.	स्तर	माध्यमिक	उच्च माध्यमिक	योग
1.	राजकीय	204	122	326
2.	अनुदानित	01	03	04
3.	गैर सरकारी	215	59	274

8.1.4 नागौर जिले में छात्र-छात्राओं का नामांकन निम्न प्रकार से है :-

क्र.सं.	कक्षा	छात्र	छात्रा	योग
1.	6 से 8 तक	44955	22370	67325
2.	9 से 10 तक	45692	19138	64830
3.	11 से 12 तक	17076	4950	22026
योग		107723	46458	154181

8.1.5 वर्तमान में अध्यापकों की संख्या

माध्यमिक स्तर			उच्च माध्यमिक स्तर		
पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
2467	359	2826	1707	391	2098

माध्यमिक सेट अप में कार्यरत कुल शिक्षक संख्या 4924 है।

8.1.6 राजकीय विद्यालय क्रमोन्नति स्थिति

स्तर	वर्ष 1991	वर्ष 2001	वर्ष 2005
माध्यमिक	120	175	204
उच्च माध्यमिक	28	81	122

8-2 | ol f'k{kk vfhk; ku ds y{; grq igp &

- जिले के ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक 2 किमी परिधि में एवं 500 तक की आबादी वाले ग्रामों में उच्च प्राथमिक विद्यालय की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मौजूदा प्रत्येक दो प्राथमिक विद्यालयों पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए जिले में इस वर्ष 60 प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किये जाने प्रस्तावित है।
- 2001 की जनसंख्या के अनुसार जिले में कुल 354 प्राथमिक विद्यालय तक की भी सुविधा से वंचित गांवों/ढाणियों/मगरों तथा वासस्थानों में उक्त सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जिले में डीपीईपी द्वारा वर्तमान में संचालित किये जा रहे वैकल्पिक विद्यालयों को औपचारिक प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किये जाने का प्रावधान है।
- दूर-दराज के क्षेत्र जहां कोई सरकारी नियमानुसार विद्यालय नहीं खोले जा सकते ऐसे स्थानों में 6 घंटे के वैकल्पिक विद्यालय/ब्रिज कोर्स खोले जाने की व्यवस्था करना।
- बाल श्रमिकों एवं पलायन करने वाले बालक बालिकाओं के लिए आवासीय ब्रिज कोर्स की व्यवस्था करना।

8-3 ; kst uk o"kl 2014&2015 ea djokbz tkuh okyh eq; xfrfof/k; ka

- नये प्राथमिक विद्यालय खोलने के प्रस्ताव – जिले में ऐसे दूरदराज के स्थान जहाँ 1 किमी. दायरे में विद्यालय नहीं है, वहाँ पर नये प्राथमिक विद्यालय खोले जाने प्रस्तावित है।
- राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत का प्रस्ताव – सर्व शिक्षा अभियान के मानदण्डों अनुसार प्रत्येक दो प्राथमिक विद्यालयों पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय खोला जाना प्रस्तावित है।
- jkt dh; mPp i kfkfed fo | ky; k dks ek/; fed ea Øekbur dk i Lrko – जिले में वर्तमान में 1024 उच्च प्राथमिक विद्यालयों पर केवल 210 माध्यमिक विद्यालय संचालित है। इस कारण दूरदराज के क्षेत्रों में विशेष रूप से बालिका को माध्यमिक स्तर की शिक्षा सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु वर्ष 2014–2015 में उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनुपात में 50 माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत किये जाने प्रस्तावित है।
- jkt dh; ek/; fed fo | ky; k dks mPp ek/; fed ea Øekbur dk i Lrko & जिले के क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के अनुपात को दृष्टि गोचर रखते हुए वर्तमान में संचालित 110 उच्च माध्यमिक विद्यालय बहुत कम है, अतः अनुपातिक दृष्टि से वर्ष 2014–2015 में 50 नये उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले जाने प्रस्तावित है।
- निर्माण कार्य:—
 - अतिरिक्त कक्षा कक्ष – जिले में करवाए गये सर्वेक्षण से यह तथ्य सामने आया है कि जिले के नामांकन के अनुपात में कक्षा-कक्षों की संख्या अपर्याप्त है। जिले में वर्तमान में प्राथमिक स्तर के 2515 विद्यालयों में 7545 कक्षाकक्ष होने चाहिए जबकि वर्तमान में इन विद्यालयों में 3925 कक्षाकक्ष ही मौजूद है साथ ही 1026 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निर्धारित मानदण्डों अनुसार 6568 कक्षाकक्ष होने चाहिए लेकिन वर्तमान में 4585 कक्षाकक्ष ही मौजूद है। सर्व शिक्षा अभियान में चूकि: सिविल कार्य हेतु राशि का प्रावधान मर्यादित है, इस कारण वांछनीय संख्या में कक्षा-कक्षों का निर्माण संभव नहीं है। अतः 300 प्राथमिक विद्यालय एवं 400 उच्च प्राथमिक विद्यालय में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण इस परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 2014–2015 में करवाए जाने का प्रावधान रखा गया है।
 - शौचालय – जिले में कराए गए सर्वेक्षण के दौरान यह तथ्य सामने आया है कि जिले में ऐसे विद्यालय की संख्या काफी अधिक है, जहां शौचालय निर्माण करवाया जाना है। कुल

1210 शौचालय रहित प्राथमिक विद्यालय एवं 338 उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 90 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्र/छात्राओं के अलग-अलग शौचालय निर्माण करवाये जाने है। इस प्रकार वर्ष 2014-2015 में 1638 शौचालय निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

- **पेयजल सुविधा** – डाईस डाटा प्रपत्र के अनुसार कुल 1120 प्राथमिक विद्यालयों एवं 395 उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 180 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्थाई रूप से पानी की सुविधा का अभाव है। वर्ष 2008-09 में 535 विद्यालयों में स्थाई जल सुविधा करवाये जाने का प्रावधान प्रस्तावित है।
- **चार दिवारी निर्माण** – वर्तमान में संचालित 1210 प्राथमिक विद्यालय 613 उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 156 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सुविधा की दृष्टि से चार दिवारी का निर्माण करवाना अति आवश्यक है। अतः ग्रामसभा के प्रस्ताव अनुसार 1979 विद्यालयों में चार दिवारी निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।
- **मिड डे मिल हेतु किचन शेड** – भारत सरकार द्वारा शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु समस्त राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मिल की व्यवस्था सुनिश्चित की है।
- **विद्यालय भवन मरम्मत** – वर्तमान में संचालित 2515 प्राथमिक विद्यालयों में से 823, 924 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से 412 एवं 309 उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में जिर्ण-शीर्ण भवनों के मरम्मत का प्रावधान भी ग्राम सभाओं से प्राप्त प्रस्तावों अनुसार किया जाना है।
- **विद्यालय में फर्नीचर/टाटपट्टी/बैंच की व्यवस्था** – वर्तमान में संचालित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में फर्नीचर एवं टाट पट्टी की व्यवस्था है। शेष प्रारम्भिक स्तर के विद्यालयों में छात्र/छात्रा आंगन पर बैठकर ही अध्ययन कर रहे हैं। अतः शैक्षिक सुविधा हेतु जिले के 3043 विद्यालयों में फर्नीचर/टाट पट्टी की व्यवस्था की जानी प्रस्तावित है।
- **अतिरिक्त अध्यापक** – वर्तमान में प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तर पर 7813 शिक्षक ही कार्यरत हैं जबकि 1:40 के दर से जिले में न्यूनतम 11000 शिक्षक होने चाहिए। इसलिए उपरोक्त अनुपात के दर से 2408 अतिरिक्त अध्यापक लगाया जाना प्रस्तावित है।

जिले में उच्च शिक्षा हेतु एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। दयानन्द सरस्वती विश्व विद्यालय के अधीन 4 महाविद्यालय क्रमशः नागौर, मेड़ता, डीडवाना एवं महिला महाविद्यालय, नागौर कार्यरत हैं। जिले में मात्र एक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान है। जिले में एक भी पॉलीटेक्नीकल कॉलेज/इंजिनियरिंग कॉलेज नहीं है। मात्र औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ही कार्यरत है, जो जिला मुख्यालय, नागौर सहित जिले में क्रमशः मेड़ता, सुजानगढ़, मौलासर एवं कुचामनसिटी में स्थापित है।